सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ₹02

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

बीजेपी और टीएमसी विधायकों में मारपीट

कानपुर, गुरुवार, 04 सितंबर, 2025
वर्षः 02, अंकः 233, पृष्ठः 8+4

इनसाइड 22 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर, एआई ने पकड़े... » Pg 07

» Pg 12

योगी सरकार बना रही 'विकसित यूपी@2047' का रोडमैप

» मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2047 तक प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का खाका तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तैयार इस भव्य विज़न डॉक्यूमेंट में न केवल आर्थिक विकास बल्कि सुरक्षा, सुशासन, सामाजिक संतुलन और सांस्कृतिक उत्थान को भी केंद्र में रखा गया है। योगी सरकार ने इस योजना को तीन मिशन, तीन थीम और 12 सेक्टरों में बांटा है। इनमें 'सुरक्षा एवं सुशासन' को सबसे अहम आधार माना गया है। सरकार का मानना है कि भयमुक्त, सुरक्षित और पारदर्शी शासन ही मजबूत अर्थव्यवस्था और सामाजिक समरसता की गारंटी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश का सपना तभी पूरा होगा जब शासन व्यवस्था भयमुक्त, सुरक्षित और पारदर्शी होगी।

सरकार का विजन-2030 और 2047 तक के लक्ष्य

2030 तक

- हर जिले में अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना।
- सभी जिलों की विकास योजनाओं और मास्टरप्लान का निर्माण।
- हर घर और संस्थान तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।
- ई-गवर्नेंस और एआई आधारित निर्णय प्रणाली से पारदर्शी शासन।

2047 तक

- यूपी को रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट में वैश्विक मानक पर पहुंचाना।
- 'जीरो एक्सीडेंट विज़न' को साकार करना।
- पूरी तरह जवाबदेह और पारदर्शी शासन व्यवस्था की स्थापना।
- स्मार्ट कनेक्टिविटी, डिजिटल ऊर्जा प्रबंधन और संतुलित विकास मॉडल।

सुरक्षा और सुशासन के स्तंभ

यूपी में शासन व्यवस्था तीन स्तंभों पर खड़ी होगी

01. **स्मार्ट गवर्नेंस** : पारदर्शी, डिजिटल और एआई आधारित शासन।
02. **स्मार्ट पुलिसिंग** : एआई निगरानी, सीसीटीवी नेटवर्क और अपराध पर जीरो टॉलरेंस।
03. **जीरो एक्सीडेंट और रोड सेफ्टी** : आधुनिक यातायात प्रबंधन और सुरक्षित परिवहन।

आर्थिक दृष्टि से महत्वाकांक्षी लक्ष्य

- 'विकसित यूपी -2047' के आर्थिक लक्ष्य भी बेहद महत्वाकांक्षी हैं।
- यूपी को 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य।
- इसके लिए राज्य को 16 फीसदी वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखनी होगी।
- वर्ष 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 26 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी।
- भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान 20 फीसदी तक बढ़ेगा।

अब तक की उपलब्धियां (2017-2025)

योगी सरकार ने बीते साढ़े आठ सालों में सुरक्षा और सुशासन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का दावा किया है-

- 2.19 लाख नए पुलिसकर्मी भर्ती और 1.53 लाख प्रमोशन।
- 243 अपराधी एनकाउंटर में ढेर, 21,023 वांछित अपराधी गिरफ्तार।
- 83,144 आरोपी गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजे।
- ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 1.04 लाख अपराधियों को सजा, जिनमें 70 को फांसी और 8,785 को आजीवन कारावास।
- महिला सुरक्षा के लिए 9,172 महिला बीट कांस्टेबल नियुक्त, 3 महिला बटालियन गठित, और 5 नई पीएसी बटालियन को मंजूरी।
- 12.42 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे पूरे प्रदेश में स्थापित।
- अपराधियों और माफियाओं की 1.44 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त।

निवेश-रोजगार पर फोकस

- सरकार का दावा है कि भयमुक्त और निवेश-हितैषी वातावरण बनाकर उद्योग और रोजगार को नई ऊंचाई दी जाएगी।
- जीआईएस-2023 में निवेश प्रस्तावों को तेज़ी से धरातल पर उतारने की प्रक्रिया जारी।
- इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, कृषि और डिजिटल सेक्टर पर विशेष फोकस।
- स्टार्टअप और एमएसएमई को प्रोत्साहन देकर रोजगार के लाखों अवसर सृजित करना।

आक्रोश

'प्रशासन भाजपा के दबाव में काम कर रहा है', प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी

इटावा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर भड़के अजय राय

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

इटावा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इटावा में कांग्रेसियों की गिरफ्तारी और उनसे मिलने न देने के विरोध में कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। उन्होंने प्रशासन पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। अजय राय ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा लिखा गया है और जेल में मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इटावा में जिस तरह कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें कारागार में कांग्रेसियों से मिलने नहीं दिया उसके बाद कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। गुरुवार को केंद्रीय कारागार में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित नौ लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे अजय राय को मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया। वहीं, जेल गेट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अजय राय ने आरोप लगाया कि प्रशासन भाजपा के दबाव में काम कर रहा है।

» पार्टी कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा लिखा गया

» पूरे प्रदेश में जन आंदोलन होगा कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे

पार्टी कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा लिखा गया और अब जेल में मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यालय में प्रवेश कर गए थे। कांग्रेस को अपना बचाव करने का अधिकार है। प्रशासन ने भाजपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के कार्यालय में घुस जाने की छूट कैसे दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रणनीति बनाई है और पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी।

चमड़ा उद्योग को बड़ी राहत: टैक्स घटा, बाजार में बढ़ेगी रौनक

» फिनिश्ड लेदर सस्ता, फुटवियर उद्योग में आई बहार

» 2030 तक चार लाख करोड़ का लक्ष्य, उद्योग को मिली नई ऊर्जा

प्रमुख संवाददाता /स्वराज इंडिया

कानपुर। चमड़ा उद्योग के लिए यह साल बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। पहले केंद्र सरकार ने बजट में 6,600 करोड़ रुपये का पैकेज दिया, फिर राज्य सरकार ने नई चर्म एवं फुटवियर नीति लागू की और अब जीएसटी काउंसिल ने राहत देते हुए फिनिश्ड लेदर पर टैक्स को 12त्न से घटाकर सिर्फ 5त्न कर दिया है। इससे निर्माताओं में उत्साह है और उनका मानना है कि घरेलू बाजार के साथ निर्यात के क्षेत्र में भी बड़ा उछाल मिलेगा।

अभी तक 1,000 रुपये तक के जूते पर 5त्न, 2,500 रुपये तक के जूते पर 12त्न और उससे ऊपर के जूते पर 18त्न जीएसटी लगता था। अब संशोधन के बाद 2,500 रुपये तक के जूते सिर्फ 5त्न टैक्स में मिलेंगे जबकि 2,500 रुपये से ऊपर के जूतों पर 18त्न ही लागू होगा।

सरकारी सौगातों से चमड़ा उद्योग में खुशहाली

कानपुर को एक जिला, एक उत्पाद योजना में चमड़ा चुना गया है और यहां 15 हजार करोड़ रुपये का घरेलू व निर्यात कारोबार होता

है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो चर्म उत्पादों का निर्यात 35 हजार करोड़ रुपये और घरेलू खपत 67 हजार करोड़ रुपये है।

चर्म निर्यात परिषद ने 2030 तक इसे चार लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. जालान का कहना है कि टैक्स दरों में बदलाव से ग्राहक और निर्माता दोनों को लाभ होगा।उन्होंने उम्मीद जताई कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में जीडीपी 8त्न को छू सकती है। वहीं, क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने कहा कि त्योहार से पहले आई यह राहत फुटवियर उद्योग के लिए सचमुच त्यौहार का तोहफा है।

चौबेपुर में गणेश विसर्जन पर उमड़ा जनसैलाब

भक्तों ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर बप्पा को दी भावभीनी विदाई, जगह-जगह हुआ भंडारा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। बुधवार को गणेश महोत्सव के समापन अवसर पर चौबेपुर क्षेत्र में गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का धूमधाम से विसर्जन किया गया। बप्पा की विदाई के दौरान नगरवासियों में आस्था और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। हजारों की संख्या में श्रद्धालु विसर्जन यात्रा में शामिल हुए और ढोल-नगाड़ों की थाप पर जमकर नाचे।सुबह से ही पूरे नगर में उत्सव का माहौल बना रहा। विसर्जन यात्रा के दौरान जगह-जगह भंडारे का आयोजन हुआ, जहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगीं। श्रद्धालुओं ने फूल-मालाओं, नारियल और आरती के साथ गणपति बप्पा का पूजन किया और 卐गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ卐 के जयघोष के बीच बप्पा को विदाई दी।भावुक कर देने वाले इस अवसर पर महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कई भक्त बप्पा की प्रतिमाओं को कंधों पर उठाए नाचते-गाते विसर्जन स्थल तक लेकर गए।पूरे आयोजन के दौरान चौबेपुर पुलिस प्रशासन सतर्क दिखाई दिया। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा और अधिकारियों ने खुद भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन की सतर्कता से विसर्जन यात्रा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई।

स्थानीय नागरिकों ने कहा कि गणेशोत्सव की विदाई भले ही भावुक रही हो, लेकिन नगर में हर चेहरे पर श्रद्धा और उल्लास का भाव साफ झलक रहा था।

एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने फूंका मंत्री ओमप्रकाश राजभर का पुतला

डीएम को सौंपा ज्ञापन, ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ कार्रवाई की मांग

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी (स्मारू), बाराबंकी में छात्रों के साथ हो रहे कथित शोषण, भ्रष्टाचार और बर्बर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर महानगर इकाई ने आज परेड चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर का पुतला दहन कर विरोध जताया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।

एबीवीपी महानगर मंत्री मयंक पासवान ने कहा—

शांतिपूर्ण छात्रों को गुंडा कहना मंत्री ओमप्रकाश राजभर की मानसिकता को दर्शाता है। यदि उन्होंने 48 घंटे के भीतर अपने बयान पर सार्वजनिक माफी नहीं मांगी, तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन को और व्यापक करेगी।

विरोध प्रदर्शन में सुधांशु, दिनेश यादव, आशुतोष, खुशी, एल्विन, उज्ज्वल, उपेंद्र, प्रभात, पीयूष, दीपक, गुंजन, राम, हर्षित, ज्ञानेंद्र, अर्जुन, प्रतिमेश, श्रेयांश, समीर, नैतिक, आयुष, आदित्य, प्रखर, अभिलाष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे।एबीवीपी का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता न होने के बावजूद विधि पाठ्यक्रमों में दाखिले दिए। छात्रों से बड़े पैमाने पर फीस वसूली और विलम्ब शुल्क के नाम पर अवैध उगाही की गई।आंदोलन कर रहे छात्रों पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पुलिस और बाहरी तत्वों की मदद से लाठीचार्ज करवाया, जिसमें कई छात्र घायल हुए।शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एबीवीपी छात्रों को गुंडा कहकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की।

एबीवीपी की मांगें

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन में चार प्रमुख मांगें रखीं—

1. लाठीचार्ज प्रकरण की जांच कर सभी दोषी पुलिसकर्मियों व बाहरी तत्वों पर मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए।

2. विधि पाठ्यक्रमों की मान्यता व फीस वसूली घोटाले की तथ्यात्मक जांच कर विश्वविद्यालय को बंद किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित किया जाए।

3. उच्च शिक्षा परिषद के सचिव द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर तत्काल कार्रवाई शुरू हो।

4. विश्वविद्यालय द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया जाए और तहसीलदार कोर्ट द्वारा लगाए गए 27.96 लाख जुर्माने की वसूली कराई जाए।

अबॉर्शन कराने आई महिला की आंत काटकर छीन ली जिंदगी!

- फर्जी डॉक्टर व पति समेत पांच पर गैर इरादतन हत्या केस दर्ज
- वर्षों के एक बहुमंजिला मकान में चल रहा था अवैध कारोबार
- एसडीएम के निर्देश पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर में अवैध अबॉर्शन के दौरान दलित महिला की मौत ने सनसनी फैला दी। खुद को रिटायर्ड सरकारी डॉक्टर बताने वाली पूनम कटियार पर आरोप है कि गर्भपात की प्रक्रिया में लापरवाही से महिला की आंत कट गई और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने पूनम, उसके पति और तीन अन्य पर गैर इरादतन हत्या और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।

शिवराजपुर निवासी दिनेश गौतम 24 अगस्त को पत्नी रेखा को गर्भपात कराने के लिए बिल्हौर स्थित पूनम कटियार के क्लीनिक ले गया । आरोप है कि तीन मंजिला मकान में चल रहे इस गुप्त क्लीनिक में पूनम ने पति व तीन अन्य की मौजूदगी में अबॉर्शन किया। लापरवाही इतनी गंभीर रही कि महिला की छोटी आंत ही कट गई।

घर लौटते ही रेखा को असहनीय दर्द शुरू हुआ। तबियत बिगड़ने पर परिजन पहले उसे आरएस अस्पताल कल्याणपुर और फिर मैट्रो अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि गर्भपात गलत तरीके से किया गया और आंत कट जाने से हालत नाजुक हो गई। इलाज के दौरान रेखा की मौत हो गई। पीड़ित पति ने एसीपी व एसडीएम बिल्हौर को तहरीर देकर आरोप लगाया कि पूनम कटियार ने झूठ बोलकर खुद को सरकारी रिटायर्ड डॉक्टर बताया और उसकी पत्नी की जान ले ली। एसडीएम के आदेश पर सीएचसी अधीक्षक की टीम ने मौके पर जांच की। वहां से खून से सनी रुई, ग्लव्स, गलत दवाएं और उपकरण बरामद हुए। फर्जी क्लीनिक को तत्काल सील कर दिया गया। इसके बाद इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने पूनम कटियार, उसके पति और तीन अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अवैध रूप से संचालित क्लीनिक को अधिकारीयों ने सीज किया।

जिंदगियों से खिलवाड़ का अवैध कारोबार

स्थानीय लोगों का कहना है कि पूनम कटियार का यह अवैध क्लीनिक कोई नया नहीं था। यह सालों से इसी तरह संचालित हो रहा था। कई महिलाएं यहां पहुंचती रहीं और मौत का यह धंधा बेरोकटोक चलता रहा। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण में यह कारोबार सालों से चलता रहा? क्या स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी, या फिर सब लोग जानबूझकर चुप्पी साधे रहे?

बेरहमी तीन युवक गिरफ्तार, अफवाहों ने किया इंसानियत को शर्मसार

चोर समझ युवक को दी तालिबानी सज़ा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

शिवराजपुर (कानपुर)। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव में अफवाहों ने इंसानियत का गला घोंट दिया। गांव में चोर-बदमाश घुस आने की फुसफुसाहट क्या फैली कि ग्रामीणों ने शक के दायरे में आए एक युवक को पकड़ लिया और खंभे से बांधकर तालिबानी अंदाज़ में बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हैवानियत की हद तो तब पार हो गई, जब इस करतूत का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि स्वराज इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, मगर इस सनसनीखेज़ फुटेज ने पुलिस-प्रशासन में खलबली मचा दी।

एसीपी अमरनाथ यादव ने वीडियो सामने आते ही तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। इंस्पेक्टर शिवराजपुर के मुताबिक चौकीदार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों मलखान, हेमंत और जगदीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों से पूछताछ जारी है, वहीं पुलिस ने घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश भी तेज कर दी गई है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अफवाहों के आधार पर तालिबानी सज़ा देना न केवल घोर अपराध है बल्कि समाज में अराजकता फैलाने जैसा कृत्य है। गुनहगार किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे।

भटपुरा गांव में खंभे से बांधकर युवक की तालिबानी अंदाज़ में पिटाई करते ग्रामीण।

चोर समझकर पीटे गए दोस्तों के मामले में ग्राम प्रधान समेत 12 पर मुकदमा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। भवानीपुर गांव में जन्मदिन की पार्टी मनाने आए दोस्तों की पिटाई के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। गांव के प्रधान रंजीत पाल समेत 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पार्टी से भटके युवक को न सिर्फ बिजली के खंभे से बांधकर पीटा बल्कि उसके साथियों और बीच-बचाव करने पहुंची पुलिस से भी धक्का-मुक्की की। गौरतलब है कि 29 अगस्त की रात कन्नौज से आए पांच दोस्त जीटी रोड स्थित एक होटल में जन्मदिन की पार्टी कर रहे थे। खाने-पीने के दौरान विवाद हुआ तो सिद्धांत राय नाराज होकर होटल से निकल गया। रास्ता भटककर वह भवानीपुर पहुंचा,जहां ग्रामीणों ने उसे चोर समझ लिया और पकड़कर खंभे से बांधकर पीट दिया। बाकी साथी पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट हुई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस से भी हाथापाई की गई। इस मामले में गांव के चौकीदार पुत्तन की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान रंजीत पाल समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह राठौर ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।

सिंघौली में चोरी, महिला घायल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। अरौल थाना क्षेत्र के सिंघौली गांव में बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। चोर 25 हजार रुपये नकद और एक सोने की अंगूठी चोरी कर ले गए। इसी दौरान खटपट की आवाज सुनकर जागी घर की एक महिला को चोर ने चाकू से घायल कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इन दिनों चोरी और लूट की घटनाओं के चलते लोग परेशान हैं और रातभर पहरा देने को मजबूर हैं। उधर, पुलिस इस घटना को संदिग्ध मानते हुए जांच कर रही है।

सम्पादकीय

रैगिंग के बदलते तरीकों की हो निगरानी

यह विडंबना है कि नियामक संस्था की सख्ती और शिक्षण संस्थाओं की सक्रियता के बावजूद रैगिंग का रोग काबू में नहीं आ रहा है। जब-तब कुछ छात्रों के आत्महत्या करने और कई मामलों में दोषी छात्रों के निलंबन व पुलिस कार्रवाई के मामले भी अक्सर उजागर होते हैं, मगर मर्ज है कि लाइलाज होता जा रहा है। सीनियर छात्र नये छात्रों को परेशान करने के लिये नये-नये तौर-तरीके तलाश लेते हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले यूजीसी ने देश के 89 उच्च शिक्षा संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी करके सख्त हिदायत दी है कि रैगिंग पर नियंत्रण करने वाले नियमों को सख्ती से क्यों लागू नहीं किया गया। यूजीसी ने इन उच्च शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों को चेताया है कि इन संस्थाओं के परिसर में छात्रों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। अब जब देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में नये छात्रों के प्रवेश का सिलसिला आरंभ होने वाला है, यूजीसी ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। उसने रैगिंग के नये तौर-तरीकों से कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया है। दरअसल, विभिन्न प्रसंगों में देखा गया है कि सीनियर छात्र नये छात्रों को परेशान करने के लिये नये तौर-तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजीसी के मुताबिक, ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं कि सीनियर छात्र अनौपचारिक व्हाट्सएप समूह बनाकर नये छात्रों को उससे जुड़ने के लिये बाध्य करते हैं। फिर छात्रों के मानसिक उत्पीड़न का सिलसिला आरंभ हो जाता है। यही वजह है कि यूजीसी ने नये छात्रों को परेशान करने के इस नये तरीके के प्रति शिक्षा संस्थानों के अधिकारियों को चेताया है कि ऐसे मामले भी रैगिंग विरोधी नियमों के दायरे में आते हैं। इन मामलों में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थानों व कालेजों को रैगिंग मुक्त वातावरण बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

निश्चित रूप से नया सत्र शुरू होने से पहले यूजीसी की यह सक्रियता व सार्थक पहल स्वागत योग्य है। ऐसे में उच्च शिक्षण संस्थानों और कालेज प्रबंधन का दायित्व बनता है कि वे रैगिंग के नये तौर-तरीकों की सतर्कता से निगरानी करें। ताकि इसका इस्तेमाल नये छात्रों को आतंकित करने तथा अपमानित करने के लिए न किया जा सके। यह विडंबना ही है कि सीनियर छात्र नये छात्रों को परेशान करने के लिये नये-नये तरीके निकाल लेते हैं। यही वजह है कि नये छात्रों की शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं। पिछले सत्र में शिकायतें मिलीं कि सीनियर छात्र अनौपचारिक व्हाट्सएप ग्रुप में नये छात्रों को शामिल करके उन्हें धमकाते हैं।

उन पर अपमानजनक नियम थोपते हैं। उन पर न केवल व्यंग्य करते हैं बल्कि गालियां भी देते हैं। ऐसे में नये भविष्य के लिए उत्साहित छात्र नयी परिस्थितियों में खुद को ढालने की कोशिश में विफल हो जाते हैं। उन्हें कई तरह से मानसिक व शारीरिक कष्टों तक का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि भयाक्रांत होने से कई छात्र विश्वविद्यालय या कालेज छोड़ने तक के लिए बाध्य हो जाते हैं। कुछ छात्र लंबे तनाव के बाद डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। निस्संदेह, शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कहीं न कहीं विश्वविद्यालय व कालेज प्रशासन की शिथिलता व उदासीनता भी सीनियर छात्रों की गुंडाई को बढ़ावा देती है। जिसके लिये जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

संघर्ष की डगर पर डर-शर्म की टूटती बाधाएं

क्षमा शर्मा

महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों के आंकड़े चिंताजनक हैं। साल 2012 में निर्भया कांड के बाद कई सकारात्मक कदमों के बावजूद इस दिशा में काम अधूरा है। हाल की कई घटनाओं में यह उजागर भी हुआ। लड़ाई नियंत्रण वाली सोच और सहमति के बीच है। भारत की बेटियां दशकों से समानता के लिए लड़ रही हैं। वर्णिका कुंडू, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसी महिलाएं लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं।इस महीने चार दृश्य ऐसे रहे जो भारत में महिला और फीमेल सेक्सुएलिटी की दशा को परिभाषित करते हैं।

पहला, ओडिशा के बालासोर में एक युवा कॉलेज छात्रा ने आत्महत्या कर ली, वह अपने प्रोफेसर द्वारा 'संबंध' बनाने के दबावों का विरोध कर रही थी। दूसरा, वायरल हुई एक वीडियो में एक ट्रक पर भगवा लहंगा-चोली पहनकर नाचती दो महिलाओं द्वारा कांवड़ियों का मनोरंजन करने वाला दृश्य, जो बॉलीवुड की वास्तविक जीवन में नकल का बिल्कुल सही उदाहरण है। तीसरी, सेंसर बोर्ड द्वारा सुपरमैन और उसकी प्रेमिका लोइस लेन के बीच 33 सेकंड लंबे चुंबन दृश्य को काट देना, क्योंकि उसे लगता है कि यह भारतीय दर्शकों के लिहाज से 'अत्यधिक कामुक' है।और चौथा दृश्य रहा, हरियाणा भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे विकास को सहायक महाधिवक्ता नियुक्त किया जाना, इस तथ्य के बावजूद कि उस पर 2017 में, चंडीगढ़ में, एक युवती वर्णिका कुंडू का पीछा करने और अपहरण के प्रयास का आरोप है। तब वह पांच महीने जेल में भी रहा था। यह आपराधिक मामला है। आठ साल हो गए, लेकिन मुकदमा अभी भी चला ही जा रहा। शायद चंडीगढ़ में न्याय का पहिया बहुत धीरे घूमता है शायद हरियाणा के बारे में कुछ है। साथ ही, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में भी, जहां महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध हर साल बढ़ रहे हैं। हम में से जिनकी याद्दाश्त ठीक है, उन्हें दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक लड़की के साथ हुआ सामूहिक बलात्कार याद होगा, जिसे हम निर्भया के नाम से जानते हैं – हालांकि असली नाम कुछ और था – एक ऐसी लड़की जो आलोक और साहस दोनों से परिपूर्ण थी – यह घटना उस लड़ाई में महत्वपूर्ण मोड़ रही, जो भारत की बेटियां दशकों से समानता के लिए लड़ती आई हैं।

प्रधानमंत्री मोदी को उस समय भान था कि दिल्ली गैंगरेप कांड कांग्रेस को 2014 के आम चुनाव में देशभर में और फिर अगले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार का बड़ा कारण रहा। तभी मोदी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का ऐसा नारा दिया, जो पूरे देश में गूंज उठा। उन्होंने महिलाओं को सरकारी योजनाओं के पहले लाभार्थियों के रूप में, सबसे आगे रखा, उन्हें एक वोट बैंक और यहां तक कि कोटा में तब्दील कर दिया – भविष्य में किसी समय 33 प्रतिशत महिला सांसद चुने जाने की उम्मीद है, हालांकि यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं कि कब। फिर भी, यह एक प्रण है और कोई भी इससे पीछे नहीं हट सकता। 2018 में, वर्णिका कुंडू द्वारा चंडीगढ़ के एक थाने में विकास बराला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के एक साल बाद, हर 15 मिनट में एक बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज हुई। आंकड़ों में राजनेताओं द्वारा खुद को दोष-मुक्त रखना भी अंतर्निहित है। यौन उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न के प्रयास के आरोपियों की सूची में विकास बराला का नाम नवीनतम है। अब तक की इस सूची में पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह, कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी, फिलहाल निलंबित पूर्व जनता दल-एस सांसद प्रज्वल रेवन्ना, पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर व कई अन्य नाम शामिल हैं।जिस एक कारण से शायद राजनेताओं को लगता है कि वे बच निकलेंगे, वह है कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम का पंजीकृत राजनीतिक दलों पर लागू नहीं होना – बीते शुक्रवार ही सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

आंतरिक ध्वनि चिकित्सा है गुनगुनाना

अंर्तमन

डा0 जगदीप सिंह

जब बच्चा छोटा होता है तो मां बच्चे को लोरी गाकर सुनाती है। लोरी गाते-गाते वह कई बार गुनगुनाती भी है। यह गुनगुनाना न केवल मां-बच्चे को मानसिक शांति प्रदान करता है, अपितु उनके आपसी बंधन को भी मजबूत करता है।क्या आपने काम करते समय कोई गीत या ध्वनि गुनगुनाई है। अवश्य गुनगुनाई होगी। आपको यह पता होना चाहिए कि गुनगुनाना मात्र छोटी-सी बात नहीं है, अपितु इस गुनगुनाहट में बहुत सारे जीवन के सकारात्मक सार छिपे हुए हैं। यह गुनगुनाहट 'आंतरिक ध्वनि चिकित्सा' है जो व्यक्ति के जीवन के टूटे-फूटे तारों की मरम्मत करती है और उनके अंदर एक नई ऊर्जा एवं ध्वनि का संचार करती है।

नादब्रह्म, ध्यान में गुंजार ऊर्जा का असीम स्रोत है। इस संदर्भ में ओशो कहते हैं कि, 'हां, यह ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। हम अपने जीवन के स्रोतों को नहीं जानते और यह नहीं जानते कि उन स्रोतों से कैसे जुड़ें?' शोध बताते हैं कि 'भंवरे की तरह गुनगुनाना यानी कि हमिंग करने से न केवल तनाव कम होता है, अपितु इससे मूड भी सकारात्मक होता है। शरीर के अंदर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और पेट संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। स्वीडिश वैज्ञानिकों ने भी अपने एक शोध में यह पाया कि 'गुनगुनाने से मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा में सुधार होता है।'

जब हमारा तन किसी ध्वनि को मन से गुनगुनाता है तो तन-मन का कंपन एक तालमेल में आ जाता है और उनका संघर्ष खत्म हो जाता है। इस संघर्ष के खत्म होने से ऊर्जा का ह्रास होने से बच जाता है। मन को शांति का अहसास होता है। गुनगुनाना हमारे मस्तिष्क की वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करता है, जो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम से जुड़ी हुई होती है। इससे तनाव कम होता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ जाती है। इससे सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे लाभकारी न्यूरो हार्मोंस का रिसाव बढ़ता है। ये दोनों ही हॉर्मोन खुशी उत्पन्न करने वाले माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति से व्यक्ति को खुशी एवं सुख का अनुभव होता है। गुनगुनाना संगीत का ही एक भाग है। भारतीय संगीत और इसके रागों में रोगों को दूर करने की अद्भुत शक्ति होती है।प्राचीन काल में राजा-महाराजा जब युद्ध से लौट कर आते थे तो वे तन-मन से शिथिल और क्लान्त रहते थे। ऐसे में वे संगीतकारों को राजदरबार में बुलाकर उनसे राग सुना करते थे। कई बार तो वे गायक के साथ-साथ गुनगुनाते भी थे। इस गुनगुनाहट से उनकी थकान, चिंता सब गायब हो जाती थी तो और वे फिर से तरोताजा हो जाते थे। अपने अंदर ऊर्जा एवं स्फूर्ति का संचार कर वे राजकाज संभालते थे और गुनगुनाते हुए प्रजा के दुख दूर करते थे। अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक तानसेन को संगीत में उच्च कोटि की सिद्धि प्राप्त थी। यह भी किंवदंती सुनने को मिलती है कि जब वे राग दीपक गाते थे तो उसकी गर्मी से दीपक स्वयं जल उठते थे। इसी तरह मेघ मल्हार गाने से झमाझम बारिश होने लगती थी। इससे ही यह स्पष्ट हो जाता है कि संगीत और गुनगुनाहट में असीम शक्ति है। इस शक्ति से मनुष्य तो क्या पृथ्वी और प्रकृति तक झूमने लगते हैं।मनोचिकित्सक मानते हैं कि रागों में व्यक्ति के तन-मन के रोगों को दूर की जादुई शक्ति छिपी है। संगीत और गुनगुनाहट को चिकित्सा प्रणाली में शामिल कर रोगियों को ठीक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तोड़ी, भूपाली, अहीर भैरव राग सर्दी-जुकाम, सिरदर्द और उच्च रक्तचाप से राहत देते हैं। शिवरंजनी राग सुनने से याददाश्त तेज होती है और स्मृति लोप की समस्या दूर होती है। राग भैरवी सर्दी, कफ और दांत दर्द से राहत देता है। चंद्रकौंस राग हृदय रोग और मधुमेह के लिए उपचारदायक है। राग दरबारी तनाव दूर करता है। राग बिहाग और बहार गहरी मधुर नींद के लिए लाभदायक है।

जगन्नाथ गली में धूमधाम से मना 16वां श्री गणेश महोत्सव

» हजारों श्रद्धालुओं ने चखा प्रसाद

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। शहर के जर्नलगंज स्थित जगन्नाथ वाली गली में इस वर्ष 16वां श्री गणेश महोत्सव बड़े हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। महोत्सव के दौरान 3 सितंबर को राजगद्दी कार्यक्रम संपन्न हुआ। राजगद्दी के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया।कार्यक्रम के दौरान पूरा वातावरण फगणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने गणेश भगवान की आराधना कर सुख-समृद्धि और मंगलकामना की।इस आयोजन की मुख्य संयोजक श्रीमती चंद्रकला और अंबिका प्रसाद अग्रवाल रहे। श्रद्धालुओं ने उनके द्वारा किए गए आयोजन की सराहना की और कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी गणेश महोत्सव का कार्यक्रम भक्तिमय और अनुकरणीय रहा।

सेंट्रल पर कैटरिंग सेवाओं की हुई जांच

जांच के दौरान 10,150 रुपये का जुर्माना वसूला - 14 अवैध वेंडर पकड़े गए

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर मध्य रेलवे द्वारा कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर विशेष अभियान चलाया गया। उप मुख्य यातायात प्रबंधक आशुतोष सिंह के निर्देशन में हुए इस अभियान में कैटरिंग सेवाओं की गहन जांच की गई।

यात्रियों और आगंतुकों से फीडबैक फॉर्म भरवाए गए, जिसमें भोजन की गुणवत्ता, दरों और स्वच्छता को लेकर सुझाव प्राप्त हुए। औसतन हर शिफ्ट में 20 से अधिक फीडबैक दर्ज किए गए। इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर कैटरिंग सेवाओं का मूल्यांकन किया गया।जांच के दौरान 10,150 का ऑन-द-स्पॉट जुर्माना वसूला गया तथा 14 अवैध वेंडरों को रेल सुरक्षा बल के हवाले किया गया। सभी स्टॉल संचालकों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल आवंटित स्थान का ही उपयोग करें और यात्रियों को ताजा एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन ही उपलब्ध कराएं।

रेलवे प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कहीं भी ओवरचार्जिंग, गंदगी या घटिया भोजन परोसे जाने की शिकायत मिली तो दोषियों पर सख्त कार्यवाही होगी। न केवल जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि जरूरत पड़ने पर उनके अनुबंध भी रद्द कर दिए जाएंगे।

उप मुख्य यातायात प्रबंधक आशुतोष सिंह ने यात्रियों से अपील की कि वे भोजन या पेय पदार्थ लेते समय बिल अवश्य लें और पैकेज पर अंकित मूल्य की जांच करें। यदि मूल्य और वसूली गई राशि में अंतर हो तो तुरंत रेलवे स्टाफ को सूचित करें।

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे।

उन्नाव समेत छह जिलों में 22 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर, एआई ने पकड़े

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायतवार संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची ऑनलाइन जारी की है। बीएलओ सभी मतदाताओं का सत्यापन करने के बाद अपनी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को सौपेंगे। सही पाए जाने वाले मतदाता के आधार कार्ड के अंतिम चार अंकों को सूची पर दर्ज करेंगे।

बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मामला सुर्खियों में है। इस बीच उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से कराई गई जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बुंदेलखंड और कानपुर के आसपास के जिलों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के डुप्लीकेट नाम पाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 13 लाख डुप्लीकेट नाम

हरदोई में हैं। सिर्फ छह जिलों में 20 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर हैं।बांदा में डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या एक लाख से ज्यादा बताई जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भेजी गई सूची में इनके नामों का खुलासा हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारियों के आदेश पर डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची सत्यापन कराने के लिए बीएलओ को सौंप दी गई है। अब बीएलओ घर-घर जाकर इन मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और नई मतदाता सूची तैयार करेंगे। यह सूची एआई की मदद से तैयार की गई है।आधार कार्ड के अंतिम चार अंकों को सूची पर दर्ज करेंगे

कुछ वोटर ऐसे भी मिले हैं] जो शहर के साथ ही गांव में भी मतदान करते आ रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायतवार संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची ऑनलाइन जारी की है। बीएलओ सभी मतदाताओं का सत्यापन करने के बाद अपनी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को सौपेंगे। सही पाए जाने वाले मतदाता के आधार कार्ड के अंतिम चार अंकों को सूची पर दर्ज करेंगे। न मिलने वाले मतदाता के नाम के आगे न लिखा जाएगा, ताकि उन नामों को सूची से हटाया जा सके। इन सभी मतदाताओं के भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए सभी ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारियों को नोडल बनाया गया है। अब मतदाता सूची में एक व्यक्ति या महिला का एक ही जगह वोट रह पाएगा। डुप्लीकेट वोटों को सत्यापन के बाद सूची से हटा दिया जाएगा।

यूपी को देश की नंबर वन अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। 1960 तक उत्तर प्रदेश का देश की अर्थव्यवस्था में 14 फीसदी योगदान रहता था। फिर सरकारें बदलीं और धीरे-धीरे यह योगदान केवल सात फीसदी रह गया। यह बीमारू प्रदेश बनकर रह गया लेकिन पिछले आठ वर्षों में प्रदेश तरक्की कर रहा है और एक बार फिर देश में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जल्द ही इसे देश की नंबर वन अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी है। यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईआईटी में चल रहे समन्वय कार्यक्रम के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, साइबर सुरक्षा, सस्टेनबिलिटी के साथ कृषि, जल संसाधन पर काम हो रहा है। 2017 में सिर्फ लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर में साइबर थाना थे। वर्तमान में सभी 75 जिलों में साइबर थाना और सभी 1583 थानों में हेल्प डेस्क बनी है। महोबा के किसान अब साल में 5,000 नहीं 50,000 रुपये कमा रहे हैं। छह करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे के बजाय सामान्य श्रेणी में आ गए हैं।

ऑडीटोरियम में आयोजित फ्लैगशिप कॉरपोरेट-एकेडमिया समिट समन्वय का शुभारंभ मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, टीसीएस के सीटीओ डॉ. हैरिस विन, संस्थान के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल व उप निदेशक प्रो. बृजभूषण ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17वीं शताब्दी तक भारत की अर्थव्यवस्था नंबर एक रही। देश ग्लोबल जीडीपी में 25 फीसदी योगदान देता था मगर 1947 तक यह योगदान केवल दो फीसदी ही रह गया। पिछले 11 वर्षों में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयास से भारत दुनिया में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है जबकि अगले दो वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी है।

पिछली सरकारों में अकादमिक संस्थानों में रिसर्च केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित थीं। सामाजिक सरोकार से कोई लेना देना नहीं था। जबकि अब संस्थान देश की समस्याओं को तकनीक रूप से सुलझाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने आईआईटी के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल के गणितीय मॉडल की तारीफ की। कहा कि सभी में योग्यता है बस सही योजक की जरूरत है। यह कार्यक्रम ऐसे ही योजक का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक को बढ़ावा देना जरूरी है ।

ग्राम पंचायत ररौंख में फर्जी भुगतान का आरोप, हाईकोर्ट आदेश की अनदेखी

» पूर्व समिति संचालक ने डीपीआरओ पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

» डीएम से जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिले की ग्राम पंचायत ररौंख (विकासखंड संदलपुर) में सरकारी धन के दुरुपयोग और उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना का मामला उजागर हुआ है। ग्राम पंचायत की पूर्व समिति संचालक अंजू पत्नी अवधेश मिश्रा ने जिला अधिकारी को पत्र भेजकर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) ने न केवल न्यायालय के आदेशों को नजरअंदाज किया बल्कि फर्जी और अधूरे कार्यों का लाखों रुपये का भुगतान भी करा दिया।

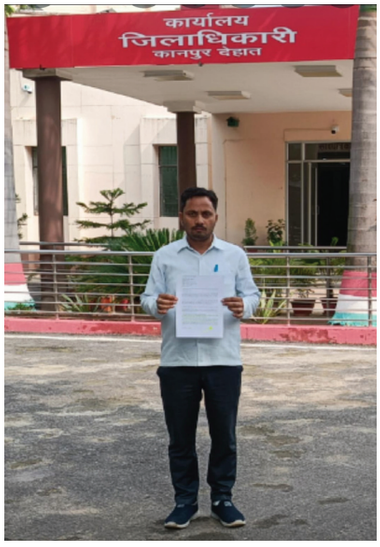

अंजू का कहना है कि 6 जून 2024 को उन्हें जिलाधिकारी के आदेशानुसार समिति संचालक नामित किया गया था। लेकिन निजी स्वार्थ और दबाव में आकर डीपीआरओ ने विरोधी पक्ष की निराधार शिकायत के आधार पर उन्हें हटा दिया और शिकायतकर्ता मुलायम सिंह को समिति संचालक बना दिया। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए अंजू ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर 15 मई 2025 को न्यायालय ने आदेश दिया कि मामले पर पुनर्विचार कर नया आदेश पारित किया जाए और प्रार्थिनी को भी सुना जाए।

लाखों की निकासी पर सवाल, डीएम से जांच की मांग

अंजू का आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद डीपीआरओ ने न तो उन्हें सुना और न ही पारदर्शी तरीके से आदेश पारित किया। इसके विपरीत, 18 जून 2025 को एक बार फिर मुलायम सिंह को समिति संचालक नियुक्त कर दिया गया। इस बीच, 29 मई 2025 को कथित रूप से लाखों रुपये का भुगतान ग्राम पंचायत से करा दिया गया।उच्च न्यायालय ने 22 अगस्त 2025 को डीपीआरओ के आदेश को निरस्त करते हुए स्पष्ट कहा कि अंजू को सुनकर ही नया आदेश पारित किया जाए और रिपोर्ट न्यायालय को दी जाए। लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी 29 अगस्त 2025 को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भारी भरकम भुगतान करा दिया गया, जो सीधा-सीधा न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।अंजू ने डीएम कानपुर देहात से मांग की है कि पूरे मामले की जांच जिला स्तरीय टीएसी टीम से कराई जाए, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और सरकारी धन की वसूली कराई जाए। इस प्रकरण ने पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार और न्यायालय के आदेशों की खुलेआम अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कानपुर देहात में मुठभेड़:अपहरण के प्रयास के दो आरोपी गिरफ्तार

» पैर में गोली लगने से दोनों हुए घायल, पुलिस ने दबोचा

» तमंचे, कारतूस, बाइक और मोबाइल बरामद, तीसरे साथी की तलाश जारी

स्वराज इंडिया न्यूज यूरो

कानपुर देहात,माती। गजनेर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में अपहरण के प्रयास के दो आरोपितों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के पास से एक बाइक, दो तमंचे, तीन खोखा, चार जिंदा कारतूस और दो मोबाइल बरामद हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस पूछताछ कर रही है।30 अगस्त को गजनेर क्षेत्र के बखरिया गांव के पास कार सवार बदमाशों ने स्कूटी से घर लौट रहे सूबेदार और उनकी पत्नी रेखा का अपहरण करने की कोशिश की थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही थी।

पुलिस की घेराबंदी में फंसे बदमाश

बुधवार रात गश्त के दौरान इंस्पेक्टर जनार्दन प्रताप सिंह को सूचना मिली कि अपहरण के प्रयास में शामिल दो आरोपी बाइक से मनेथू, लोहारी होते हुए रायपुर की ओर जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने गोगूमऊ-लोहारी के बीच सराय मोड़ पर चेकिंग शुरू की। कुछ देर बाद वहां पहुंचे बाइक सवार दोनों युवक पुलिस को देखकर भागने लगे और पीछा करने पर पुलिस पर फायर झोंक दिया।जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली दोनों आरोपितों के पैर में लगी, जिससे वे घायल होकर गिर पड़े। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सूर्यकांत चौरसिया उर्फ सूर्या (निवासी ग्राम डोड़वा जमौली, थाना बिल्हौर) और अर्जुन मिश्रा उर्फ कन्हैया (निवासी नई लेबर कॉलोनी, दादा नगर, थाना गोविंद नगर, कानपुर) के रूप में हुई। दोनों ने 30 अगस्त को हुए अपहरण प्रयास की घटना स्वीकार की है।सीओ सदर संजय वर्मा ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में घटना में शामिल अपने एक और साथी का नाम भी बताया है। फिलहाल पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश में जुटी है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादकः अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

त्योहारों की सुरक्षा पर एसपी की सख्ती, घाट से लेकर गलियों तक पुख्ता इंतजाम

» बरौर थाने का दौरा कर दुर्वासा आश्रम व घाट का निरीक्षण

» ड्रोन निगरानी, फ्लैग मार्च और बचाव उपकरणों की व्यवस्था पर जोर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। आगामी गणेश विसर्जन, बारावफात और अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने बुधवार को बरौर थाना क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दुर्वासा ऋषि आश्रम और घाट का विशेष निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया।

एसपी ने स्थानीय पुलिस और नागरिकों से मुलाकात कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने खासकर भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को दुरुस्त रखने पर जोर दिया। घाट क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे, लाइफ जैकेट और बचाव उपकरण हर हाल में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

ड्रोन व फ्लैग मार्च से बढ़ेगी सुरक्षा

पुलिस अधीक्षक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को घाट पर पीआरवी (पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल) और ड्रोन कैमरों से निगरानी सुनिश्चित करने के आदेश दिए। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकालने के निर्देश दिए, ताकि लोगों में सुरक्षा का माहौल बन सके।उन्होंने जनता से अपील की कि सभी त्योहार आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं। साथ ही यह भी कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत डायल 112 या नजदीकी थाने को दें, ताकि पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सके।

बिना मान्यता के धड़ल्ले से चल रहे स्कूल, शिक्षा विभाग बना मूकदर्शक

» नोटिस के बाद भी नहीं थमा संचालन

» मलासा ब्लॉक के टीएस पब्लिक स्कूल समेत दर्जनों पर कार्रवाई ठप

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। शासन के सख्त आदेशों के बावजूद जनपद में बिना मान्यता के संचालित हो रहे स्कूलों पर कार्रवाई ठप है। शिक्षा विभाग के अधिकारी केवल नोटिस जारी कर औपचारिकता निभा रहे हैं, जबकि स्कूल संचालक नोटिस को हवा में उड़ाकर विद्यालयों का संचालन खुलेआम कर रहे हैं।

सबसे बड़ा मामला विकास खंड मलासा के तुर्किमऊ गांव स्थित टीएस पब्लिक स्कूल का है, जो बिना मान्यता के वर्षों से चल रहा है। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक भी बार-बार लिखित शिकायत कर चुके हैं कि इन अवैध स्कूलों की वजह से सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या नहीं बढ़ पा रही है। इसके बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है।

शासन के आदेश कागजों तक सीमित

शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया जाए और नोटिस के बाद भी संचालन जारी रहने पर 10 हजार रुपये प्रतिदिन का अर्थदंड वसूला जाए। लेकिन कानपुर देहात में यह आदेश कागजों तक सीमित है।स्वराज इंडिया की पड़ताल में सामने आया कि जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में दर्जनों स्कूल बिना मानक पूरे किए संचालित हो रहे हैं। इन स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता लगातार प्रभावित हो रही है।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार मिश्रा ने मामले में कहा गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन की जानकारी नहीं थी। जांच कराई जाएगी और हर हाल में ऐसे स्कूल बंद कराए जाएंगे।

अयोध्या विकास प्राधिकरण: गुम होती पत्रावलियां और पल्ला झाड़ते अधिकारी

» भ्रष्टाचार के दलदल में धँसता प्राधिकरण, 'ईमानदारी' हो रही बेअसर

» प्राधिकरण का ताकतवर लेखपाल बना 'भस्मासुर

होटल मंगलम एंड रिसॉर्ट्स का मानचित्र विवादों में , तथ्यों को छिपाने का आरोप

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। पग-पग पर भ्रष्टाचार रूपी दलदल में फँसता विकास प्राधिकरणज। ईमानदारी की कलम यहाँ इतनी बौनी साबित हो रही है कि तथ्यों और न्यायालय के आदेशों को छिपाकर भी मानचित्र पास किए जा रहे हैं।सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है कि होटल मंगलम एंड रिसॉर्ट्स का मानचित्र गलत तथ्यों और वाद को छुपाकर पास करा लिया गया। इस पूरे प्रकरण में प्राधिकरण के कुछ अधिकारी तेजतर्रार वीसी की कार्यप्रणाली पर 'जंग' लगाने में जुटे दिखाई देते हैं।

ताकतवर लेखपाल कैसे बना है 'भस्मासुर' !

आरोप है कि प्राधिकरण अपने ही लेखपाल को बचाने के लिए एक के बाद एक गलतियां कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, ताकतवर लेखपाल से एक सप्ताह का स्पष्टीकरण तक नहीं लिया जा सका। भ्रष्टाचार छिपाने की इस जुगत में प्राधिकरण खुद सवालों के घेरे में है। सवाल यह उठता है कि

आखिर कौन सा दबाव है, जो वीसी फर्जी आख्या पर भी कार्यवाही नहीं कर पा रहे। न्यायालय के स्थगनादेश को छिपाकर पास कराए गए मानचित्र पर एक महीने से कार्रवाई अटकी हुई है। 21 अगस्त 2025 को दिए गए प्रार्थना पत्र पर खुद वीसी ने जांच का आदेश दिया था, मगर वह पत्र रहस्यमय तरीके से दबा दिया गया।

सचिव कहते हैं मेरे द्वारा नहीं रोका गया पत्र। ओएसडी का बयान फ़मुझ तक नहीं पहुँचा पत्र। प्रभारी मानचित्र और नियोजन लिपिक दोनों ही अनजान बने बैठे हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर वह कौन सी गुमनाम जगह है जहाँ भ्रष्टाचार से जुड़ी पत्रावलियां बार-बार गुम हो जाती हैं। गलत शपथपत्र

और साक्ष्य सामने आने के बाद भी मानचित्र जारी होना इस बात का सबूत है कि जांच सिर्फ़ 'लुका-छुपी' का खेल है। सचिव का बयान कार्यवाही कराएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे पूरे प्रकरण को और संदेहास्पद बना देता है। सूत्रों का दावा है कि इस मामले में जल्द ही साक्ष्यों के साथ प्रेस के माध्यम से बड़ा खुलासा होगा।

रामनगरी में नशे का साम्राज्य - सरकारी गाड़ी से सप्लाई चेन

» उत्तर प्रदेशसरकार लिखी स्विफ्ट डिज़ायर कार से 34 किलो गांजा बरामद

» एसटीएफ ने बाप बेटे को किया गिरफ्तार

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या ।राम के नगरी में नशे का कारोबार किस कदर अपनी जड़ें जमा चुका है, इसका ताज़ा सबूत अयोध्या एसटीएफ की सनसनीखेज़ कार्रवाई से सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार लिखी स्विफ्ट डिज़ायर कार से 34 किलो गांजा बरामद कर बाप-बेटे की गिरफ्तारी ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। सवाल अब यह है कि आखिर किन ताक़तों की शह पर यह धंधा इतना बेख़ौफ़ होकर चल रहा था?

बता दे कि राजेश अग्रहरि और उसका बेटा आशीष अग्रहरि नशे के इस गंदे खेल के नए चेहरे हैं। ये लोग उड़ीसा और बंगाल से गांजे की खेप मंगाकर अयोध्या और आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। धंधे को वैध दिखाने के लिए सरकारी कार का ठप्पा लगाया गया। यानी जनता को धोखा और सिस्टम की आंख में धूल। यह कोई छोटा-मोटा गिरोह नहीं है। स्वराज की पड़ताल में पहले भी सामने आया था कि रामनगरी से लेकर दिल्ली, मुंबई और पंजाब तक नशे की डोर जुड़ी हुई है। कॉलेजों और युवाओं को शिकार बनाने वाली यह चेन अब इतनी

संगठित हो चुकी है कि सरकारी ठप्पा भी उसके लिए महज़ मुखौटा है।

प्रभारी डिप्टी एसपी प्रमेश कुमार शुक्ला और उपनिरीक्षक सौरभ मिश्रा की टीम ने इस तस्करी को पकड़कर बड़ी राहत दी है। बरामद माल और आरोपियों को एनसीबी गोरखपुर यूनिट को सौंप दिया गया है। एनसीबी ने केस दर्ज कर कैंट थाने को सूचना दी। लेकिन सवाल वही क्या केवल बाप-बेटे पर कार्रवाई से नशे का साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा?क्या इनके पीछे कोई बड़े संरक्षक हैं, जिनकी पहचान से पर्दा उठना बाकी है? और सबसे बड़ाअयोध्या जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी को आखिर नशे के गढ़ में बदलने की कोशिश कौन कर रहा है? यह अब सिर्फ़ पुलिस-एनसीबी की कार्रवाई भर नहीं, बल्कि रामनगरी की आस्था पर हमला है। डीएम और एसएसपी को चाहिए कि इस नेटवर्क की हर परत उधेड़कर असली गुनहगारों को सामने लाएँ, ताकि अयोध्या की पवित्रता नशे के धुएँ में न घुटे।

बेहतर व्यवहार और जीरो टॉलरेंस होगी प्राथमिकता: एसीपी केशव कुमार चौधरी

» वर्ष 2009 बैच के आईपीएस अफसर केशव कुमार चौधरी ने बुधवार ग़ाज़ियाबाद कमिश्नरेट में दी ज्वाइनिंग

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

गाजियाबाद। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट को नया एडिशनल सीपी मिल गया है। वर्ष 2009 बैच के आईपीएस अफसर केशव कुमार चौधरी ने बुधवार देर शाम कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

श्री चौधरी ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना और जिले की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना उनका पहला लक्ष्य है। उन्होंने कहा—आम नागरिकों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। कोई भी फरियादी अपनी समस्या निसंकोच बता सकता है। कानून तोड़ने और शांति बिगाड़ने वालों से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्ती से निपटा जाएगा।

बिहार के दरभंगा जिले के मूल निवासी चौधरी अब तक कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। बतौर एसपी वे कानपुर देहात, बहराइच, जौनपुर, चित्रकूट और रामपुर सहित करीब एक दर्जन जिलों में सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा वे आगरा कमिश्नरेट में अपर पुलिस आयुक्त और झांसी रेंज में डीआईजी के रूप में भी अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं।

गाजियाबाद में उनकी तैनाती के साथ ही लोगों को उनसे पारदर्शी व संवेदनशील पुलिसिंग की उम्मीदें जुड़ गई हैं।

कुमारगंज कृषि विश्व विद्यालय में इंटरव्यू हुआ स्थगित

» अभ्यर्थियों के साथ मजाक या सिस्टम की नाकामी?

स्थायी कुलपति न होने के बाद भी क्यों शुरू की गई चयन प्रक्रिया

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अचानक ठप पड़ गई। 2 सितंबर से शुरू होकर 10 सितंबर तक चलने वाली इंटरव्यू प्रक्रिया को बीच रास्ते में स्थगित कर दिया गया। नतीजा यह कि सैकड़ों अभ्यर्थी दूर-दराज़ जिलों और अन्य राज्यों से सफर कर यहां पहुंचे और खाली हाथ, निराश होकर लौट गए।

बता दे कि कुछ अभ्यर्थियों को तो अंतिम समय में स्थगन का संदेश भेजा गया। लेकिन कई पहले ही पहुंच चुके थे, जिनका न तो इंटरव्यू हुआ और न ही खर्च की भरपाई।अभ्यर्थियों का कहना है कि यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति होनी चाहिए क्योंकि विश्वविद्यालय की अनियोजित व्यवस्था ने उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाया।

विश्वविद्यालय में फिलहाल कोई पूर्णकालिक कुलपति नहीं है। डॉ. विजेंद्र सिंह, जो डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, कृषि विश्वविद्यालय का भी अतिरिक्त प्रभार देख रहे हैं। नियमों के मुताबिक प्रभारी कुलपति भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते, बावजूद इसके नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। अब 27 अगस्त से नए कुलपति की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और अंतिम तिथि 29 सितंबर रखी गई है। ऐसे में इंटरव्यू स्थगित होना लाजमी था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रक्रिया अधूरी रहनी थी तो इंटरव्यू बुलाए ही क्यों गए? विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के बीच चर्चा है कि 5 अक्टूबर को होने वाले दीक्षांत समारोह की जिम्मेदारी भी डॉ. विजेंद्र सिंह को सौंपी गई है। ऐसे में वह कृषि विश्वविद्यालय और अवध विश्वविद्यालय दोनों की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि जब प्रभारी कुलपति से इंटरव्यू करवाना संभव नहीं था तो क्या जानबूझकर अभ्यर्थियों को भ्रमित किया गया?

भर्ती प्रकोष्ठ के चेयरमैन डॉ. अनिल कुमार से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया। उनकी चुप्पी ने सवाल और गहरा दिए हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि यह प्रशासनिक गड़बड़ी है या नियुक्ति प्रक्रिया के पीछे किसी और खेल का संकेत? अभ्यर्थियों के साथ हुए इस खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है?

सात सितंबर को पितृ पक्ष के पहले दिन चंद्रग्रहण, 21 सितंबर को विसर्जन पर लगेगा सूर्य ग्रहण

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मुरादाबाद। इस वर्ष 122 वर्ष बाद पितरों के स्मृति पर्व पितृपक्ष के आरंभ व विसर्जन पर ग्रहण का साया रहेगा। पितृपक्ष का आरंभ सात सितंबर को चंद्रग्रहण और विसर्जन पर 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। इस पर पहले व आखिरी दिन ग्रहण लगेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित केदार मुरारी ने बताया कि इस बार पितृपक्ष की पूर्णिमा 7 सितंबर को है। इस दिन चंद्रग्रहण लगेगा।चंद्र ग्रहण का स्पर्श रात्रि 9:57 बजे, मध्य रात्रि 11:41 व मोक्ष रात्रि 1:27 बजे है। चंद्र ग्रहण में नौ घंटा पूर्व सूतक लग जाता है। इसलिए इस ग्रहण का सूतक सात सितंबर रविवार को दिन में 12:57 पर लगेगा, मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। मंदिरों के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए 8 सितंबर को अपने समय से खुलेंगे।

पितृ तर्पण करने की विधि

घर की महिलाओं द्वारा शुद्ध भोजन बनवाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शरीर को शुद्ध करें, शुद्ध स्थान पर कुशा (एक प्रकार की घास) का आसन बिछा पूर्व की ओर मुंह करके देवताओं का तर्पण करें, उत्तर को मुंह करके ऋषि (दिव्य मनुष्यों का तर्पण करें और दक्षिण दिशा की ओर मुख कर पितरों का तर्पण करें, तांबे के लोटे में जल, तिल, जौ, दूध, और फूल मिलाकर सीधे हाथ के अंगूठे से पितरों को जल अर्पित करें।

आवश्यक सामान

तांबे या पीतल के पात्र में जल लेकर उसमें जौ, काले तिल, गंगाजल, सफेद फूल, कच्चा दूध और दही मिलाकर तर्पण के लिए तैयार करें, पितरों का चित्र रखकर उसके सामने एक दीया जलाएं।

इस मंत्र का करें जाप

पितृभ्य: नम: मंत्र का उच्चारण करें और अपने पूर्वजों का स्मरण करें, पहले पिता, फिर दादा, और फिर परदादा का नाम लेकर तीन-तीन बार पितरों को जल चढ़ाएं।

माता, दादी और परदादी को भी जल अर्पित करें, उनका नाम और गोत्र लेकर तर्पण करें, सुहागन स्त्री किसी भी दिन मरी हों तो उनका श्राद्ध नवमी के दिन करें।

एआई का प्रकोप : दिग्गज कंपनियों में भारी छंटनी

बेरोजगारी का खतरा गहराया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

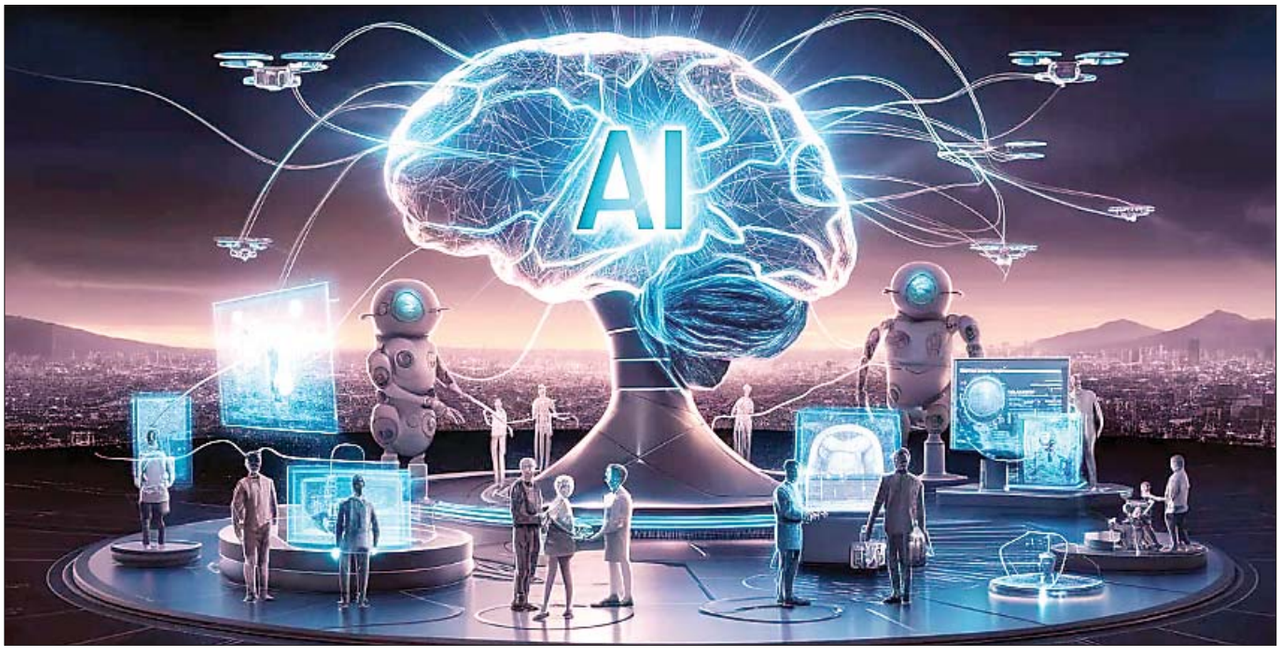

नई दिल्ली। तकनीक के लगातार बढ़ते दायरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते इस्तेमाल ने देश-दुनिया की नामचीन कंपनियों में रोजगार पर गहरा संकट खड़ा कर दिया है। बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने स्टाफ की कटौती कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि भारत सरकार समय रहते एआई को लेकर ठोस नीति और नियम नहीं बनाती, तो आने वाले दिनों में छंटनी का यह सिलसिला और तेजी पकड़ सकता है, जिससे बेरोजगारी का प्रकोप और बढ़ेगा।

अमेरिकी क्लाउड सॉफ्टवेयर कंपनी सेल्सफोर्स ने हाल ही में अपने कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट में 4,000 नौकरियों में कटौती कर दी है। कंपनी के सीईओ मार्क बेनिओफ ने पॉडकास्ट के जरिए बताया कि सपोर्ट टीम को 9,000 से घटाकर 5,000 कर दिया गया है। अब इनकी जगह एआई आधारित टूल्स काम करेंगे।

टीसीएस : बढ़ी सैलरी, लेकिन 12,000 कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता

भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने सितंबर 2025 से 80 फीसदी कर्मचारियों की सैलरी में 4.5 से 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। लेकिन इसके साथ ही कंपनी ने 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी भी की है। वजह बताई गई है–एआई, ऑटोमेशन और सख्त बेंच नीति। इस कदम का कई राज्यों में विरोध हुआ और कर्मचारियों के संगठनों ने सरकार से दखल की मांग की।

इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा में भी कटौती

2025 में सिर्फ टीसीएस और सेल्सफोर्स ही नहीं, बल्कि इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेजन, एचपी और पैनासोनिक जैसी दिग्गज कंपनियों ने भी बड़े पैमाने पर छंटनी की है।

इंटेल : 25,000 से ज्यादा नौकरियों में कटौती (लागत व एआई आधारित पुनर्गठन)।

पैनासोनिक : 10,000+ कर्मियों को निकाला (कार्यशैली में बदलाव और लागत कटौती)।

माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा : लागत कम करने और एआई अपनाने के चलते हजारों कर्मियों को हटाया।

रोजगार पर मंडरा रहा खतरा

विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनियां एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से निवेश कर रही हैं। इससे उत्पादकता तो बढ़ेगी, लेकिन नौकरियों पर खतरा मंडराता रहेगा। हालात ऐसे हैं कि आने वाले समय में कई क्षेत्रों में पारंपरिक नौकरियों की जगह पूरी तरह मशीनें ले सकती हैं।

संदिग्ध गतिविधि | **ग्रामीणों में दहशत, पुलिस छानबीन में जुटी**

रामनगरी में कई स्थानों पर आसमान में दिखे ड्रोन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

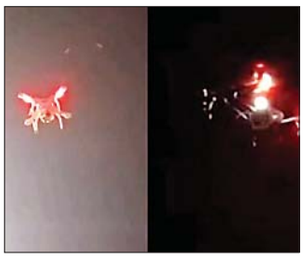

अयोध्या। यूपी के अयोध्या में बुधवार की रात मिल्कीपुर क्षेत्र के कई स्थानों पर आसमान में लोगों ने ड्रोन देखा। ड्रोन देखने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल रहा। दहशत में ग्रामीण देर रात तक जागते रहे। साथ ही इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की लेकिन, ड्रोन के संबंध में जानकारी नहीं मिल सकी।

बताया गया कि इनायत नगर के रेवना, मिल्कीपुर बाजार, खंडासा के कलुवामऊ, कोटिया, घटौली, नागीपुर, जयराजपुर, मिचकुरही, जगन्नाथपुर और तिंदौली गांव में आसमान में ड्रोन जैसी चमकदार चीजें घूमती देखी गईं। ग्रामीणों ने इसकी फोटो खींची। वीडियो भी बनाया। ड्रोन देखकर पूरे इलाके में हलचल मच गई। लोग फोन करके एक-दूसरे को ड्रोन उड़ने की जानकारी देते रहे

संदिग्ध गतिविधि मानकर दहशत बनी रही : काफी देर तक आसमान में घूमते रहे इन ड्रोन को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं और अफवाहें फैलने लगीं। किसी ने इसे सर्वे से जोड़ा तो किसी ने इसे संदिग्ध गतिविधि मानकर दहशत भी जताई। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर उत्सुकता और दहशत दोनों का माहौल बना हुआ है।

हैरिंग्टनगंज चौकी प्रभारी आशीष सिंह ने बताया कि उन्होंने भी आसमान में चमकती चीजों को देखा है। देखने में वे ड्रोन जैसे प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने आशंका जताई कि यह किसी रूट सर्वे का हिस्सा हो सकता है।

बीजेपी और टीएमसी विधायकों में मारपीट, भाजपा व्हिप चीफ घायल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कोलकाता। बंगाल विधानसभा के अंदर हंगामे की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि किसी मुद्दे को लेकर बीजेपी और टीएमसी विधायकों को बीच बहस हो गई थी जो मारपीट में बदल गई है। इसके अलावा विधानसभा के सुरक्षा गार्डों और बीजेपी विधायकों के बीच हुई हाथापाई में बीजेपी के मुख्य सचेतक घायल हो गए हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को उस वक्त हंगामा मच गया, जब बीजेपी के मुख्य सचेतक शंकर घोष और अन्य विधायकों की विधानसभा के मार्शलों और सुरक्षा कर्मियों के साथ तीखी झड़प हो गई। इस टकराव में शंकर घोष को चोटें आई हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाषण में बाधा डालने के लिए बीजेपी व्हिप चीफको सदन से निलंबित कर दिया था।

बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि मार्शलों ने उनके विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसमें शंकर घोष को गंभीर चोट आई हैं।